भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1989

उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023 (सोमवार)

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं

†1989. श्री राजू बिष्ट:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एचआईआरए (राजमार्ग, आई वे, रेलवे, एयरवे) के संबंध में संपर्क के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों के लोगों के लिए सड़क, हवाई और रेल यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

सड़क कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा सड़क (62.9 किमी) की 4-लेनिंग; अरुणाचल प्रदेश में नौगांव

बाईपास से होलोंगी (167 किमी) तक 4-लेनिंग; सिक्किम में बागराकोटे से पाक्योंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो-लेन राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल - तुइपांग एनएच-54 (351 किमी) की 2-लेनिंग; मणिपुर में एनएच-39 के इंफाल - मोरे खंड (20 किमी) की 4-लेनिंग और 75.4 किमी की 2-लेनिंग शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले सात वर्षों (2021-22 सहित, दिसंबर, 2022 तक) में कुल 4121 किमी की सड़क परियोजनाएं पूरी की गईं हैं। 1,05,518 करोड़ रु. राशि की 7545 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं जारी हैं।

वायु कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 17 हवाई अड्डों का प्रचालन किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दोन्यी पोलो हवाई अड्डे (पहले होलोंगी हवाई अड्डा) का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे; असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सिलचर हवाई अड्डे; मणिपुर में इंफाल हवाई अड्डा; मेघालय में बारापानी हवाई अड्डा और त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डा आदि का विकास जारी है।

रेल कनेक्टिविटीः पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से अब तक 19,855 करोड़ रु. राशि की 864.7 किलोमीटर लंबाई की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में, नई लाइनों के साथ-साथ दोहरीकरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह/आंशिक रूप से शामिल 2,011 किलोमीटर लंबाई के लिए 74,485 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 परियोजनाएं आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 321 किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई है और 26,874 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

जलमार्ग कनेक्टिविटी: धुबरी (बांग्लादेश सीमा) से सादिया (891 किमी) तक ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) के रूप में घोषित किया गया था। जलमार्ग को आवश्यक गहराई और चौड़ाई के फेयरवे, दिन और रात के नेविगेशन एड्स और टर्मिनलों के साथ विकसित किया जा रहा है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 461 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बराक नदी को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (एनडब्ल्यू -16) के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से असम की कछार घाटी में सिलचर, करीमगंज और बदरपुर को हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जोड़ता है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 145 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

दूरसंचार कनेक्टिविटी: दूरसंचार विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजनाएं भी शामिल हैं (i) असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) में अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज (ii) मेघालय में और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-

साथ 4जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल कनेक्टिविटी; (iii) अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी; (iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए भारत नेट और वाई-फाई कनेक्टिविटी; और (v) कॉक्स बाजार के माध्यम से बीएससीसीएल, बांग्लादेश से अगरतला तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर लेना। पूर्वोत्तर राज्यों में, 1246 गांवों को कवर करते हुए 1358 टावर स्थापित किए गए हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विभिन्न स्कीमों/पैकेजों का कार्यान्वयन कर रहा है जैसे पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम, असम के विशेष पैकेज [बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी)], पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ), एनईसी (पूर्वोत्तर परिषद) की स्कीमें और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस)। इन विकासात्मक स्कीमों/पैकेजों के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित 15,867.01 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

*****